माननीय मुख्यमंत्री, बिहार श्री नीतीश कुमार के द्वारा दिनांक–20.05.2015 को दिये गये भाषण का ट्रांसक्रिप्सन

माननीय राजस्व मंत्री श्री विजेन्द्र प्रसाद यादव जी, माननीय कृषि मंत्री श्री विजय कुमार चौधरी जी, माननीय उद्योग मंत्री श्री श्याम रजक जी, माननीय ग्रामीण विकास मंत्री, श्री श्रवण कुमार जी माननीय मंत्री कुशवाहा जी। माननीय सहकारिता मंत्री श्री जय कुमार सिंह जी, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मिडिया के प्रतिनिधिगण, रेडियो जर्नलिस्ट। आज फिर एक बार एक जगह बैठ कर इस मिटिंग में भाग लेकर मुझे खुशी हो रही है। लगभग हर बार वित्तीय वर्ष की शुरूआत में जब पहली बैठक होती है एस. एल.बी.सी. की उसमें मैंने भाग लेने की हमेशा कोशिश की है। और कई बार इस प्रकार की बैठकों में मैं अपनी राय रख चुका हूं। और बिहार में स्टेट लेबल बैंकर्स कमिटी मिटिंग के लिए भारत सरकार के कुछ प्रतिनिधि भी पधार चुके हैं। रिजर्व बैंक के पदाधिकारीगण, यहां तक कि उनके गवर्नर भी आ चुके हैं। तो कई बार आप सब लोगों के साथ बातचीत करने का अवसर मिला है और अपनी बात रखने का मौका मिला है। ये ठीक है कि पहले की तुलना में स्थिति में सुधार आया है। हम लोग हरबार सी०डी० रेशियो की बात करते थे। क्रेडिट डिपोजिट रेशियो में थोड़ा परिवर्तन आया है। कहाँ 2005–06 में ये 32 प्रतिशत् था और अब 14–15 में जाकर लगभग 44 प्रतिशत् हो गया है। पहले से बेहतरी जरूर आयी है। लेकिन अभी भी जो राष्ट्रीय औसत है 78 परसेंट का उससे हम काफी नीचे है।

और खास करके जो साउदर्न स्टेटस है वहाँ तो सी०डी० रेशियो 100 परसेंट से उपर हो गया है। मतलब पैसा जो बिहार में डिपोजिट हो रहा है उसका आधा से भी कम इस साल बिहार में क्रेडिट के रूप में लोगों का प्राप्त हो रहा है। तो इसका मतलब है जो बिहार में डिपोजिट हो रहा है। वो पैसा निश्चित तौर पर दूसरे राज्यों में, दूसरे राज्यों के लिए उपलब्ध हो रहा है। ये प्रश्न हमलोग हमेशा उठाते हैं और बैंक की तरफ से अपनी समस्याएं गिनायी जाती है। लेकिन बहरहाल ये जो द्वंद चल रहा है इस द्वंद में पहले से इम्प्रूभमेंट है। तो पहली बार बात यही कहूँगा कि थोड़ा इम्प्रूभमेंट आया है। लेकिन अभी बहुत इम्प्रूभमेंट लाने की जरूरत है। बिहार विकास के रास्ते पर चल पड़ा है। अब इसमें जो बैंकों की भूमिका है उसे तो जो विभिन्न बैंक यहां बिहार में कार्यरत है उनको अपनी भूमिका निभानी पड़ेगी। क्योंकि बगैर निवेश के कुछ नहीं हो सकता है। अब सबको मालूम है जो निवेश होता है उसकी फाइनेनसिंग होती है। और उसमें बैंकों की भूमिका होती है। तो इस प्रकार से आपकी भूमिका है। और आपकी भूमिका जबतक जब बेहतर होती चली जायेगी। तो यहां ज्यादा से ज्यादा इनवेसट्मेंट होगा। हम हमेशा शिक्षा ऋण की बात करते हैं। एडुकेशन लोन। और जब हमने यहाँ प्रश्न उठाया था तो स्वयं उस समय के वित्त मंत्री जी ने आदेश दिया था और उनके बाद उसके लिए इंतजाम किये गये थे। तो पहले से शिक्षा ऋण की स्थिति में भी सुधार आया है। लेकिन अभी भी वह बहुत ही अप्रयाप्त है। एडुकेशन लोन बहुत आवश्यक है। वो तो हमारे स्टूडेन्टस है। तो हर प्रकार से बैंकों को अपनी भूमिका निभानी चाहिए। अब बैंक अपना एनुअल क्रेडिट प्लान बनाते है। तो एनुअल क्रेडिट

प्लान बिहार जैसे राज्य के लिए कम रखा जाता है। अब पिछले साल का टारगेट था 74 थाउजेन्ड करोड़ का। ये अपने आप में राशि बहुत कम है। कोई ज्यादा राशि नहीं है, कोई .खास राशि नहीं है। रूपये की कीमत को देखते हुए ये राशि बहुत मामूली राशि है। अब इसके विरूद्ध पॉरफॉरमेन्स को हम बहुत बुरा नहीं कह सकते। लेकिन कुल मिलाकर जो एनुअल क्रेडिट प्लान बनना चाहिए वो जरा वृह्द बनना चाहिए, बड़ा बनना चाहिए। क्योंकि हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। एग्रीकल्चर ग्रोथ की संभावना बिहार में बहुत ज्यादा है। स्मॉल एण्ड मिडियम इन्टरप्राइजेज की संभावना बहुत ज्यादा है। या अन्य प्रकार की जो सेक्टर्स है जिनको आप प्राइमरी सेक्टर्स, नॉन प्राइमरी सेक्टर्स हर क्षेत्र में इसकी गुंजाइस बहुत ज्यादा है। इसलिए एनुअल क्रेडिट प्लान का साइज बड़ा होना चाहिए, ये बहुत छोटा है। जब हम बड़ा कहते हैं तो अभी जो छोटा है उससे बड़ा होना चाहिए। यानि जो दूसरे प्रदेशों का जो साइज है उस साइज तक जाना चाहते हैं तो ये तय करेगी। लेकिन इतना जरूर है कि यह एक बड़ी आबादी का राज्य है। 10 करोड़ 26 लाख तो 2011 के सेंसस के रिपोर्ट के हिसाब से है। आ उसके भी चार साल बीत गये तो आप कल्पना कर लिजिए कि जो ग्रोथ रेट है हमारा वो बहुत ज्यादा है, पोपुलेशन बहुत है। तो उस हिसाब से लगभग 11.50 करोड़ के आस पास होगा। तो इतनी बड़ी आबादी वाले राज्य में ये महज मामूली 74 हजार करोड़ रूपये का एनुअल क्रेडिट प्लान हो तो ये अप्रयाप्त है। इस लिए मेरा पहला आग्रह होगा कि क्रेडिट प्लान को, एनुअल, क्रेडिट प्लान के साइज को आप बढ़ाएं। सब सेक्टर में उदारता पूर्वक ऋण उपलब्ध कराये। एग्रीकल्चर लोन का जो हमलोगों ने बनाया

हुआ है। और एग्रीकल्चर रोड मैप के हिसाब से बिहार में एग्रीकल्चर का लोन होना चाहिए। तो उसके हर सेक्टर के लिए ऋण की गुंजाइस है। तो अभी कृषि मंत्री जी ने किसान क्रेडिट कार्ड के मसले को आपके सामने रखा। अब जो डिफॉल्टर नहीं है वैसे लोगों का तो के.सी.सी का रिन्युअल हो जाना चाहिए था। तो इस प्रकार से कई ऐसे रास्ते आप निकाल सकते हैं जिसके माध्यम से एग्रीकल्चर में ज्यादा से ज्यादा आप क्रेडिट दे सकते है। और जितने लोग हमारे यहां एग्रीकल्चर में लगे हुए है। आज भी बिहार में 76 परसेंट पोपुलेशन का, 76 परसेन्ट हिस्सा अपनी आजीविका के लिए, अपनी लाइवलीहुड के लिए एग्रीकल्चर पर निर्भर है, खेतीबारी पर निर्भर हैं और जब हम कृषि की बात करते हैं तो इसमे जो एलाइड सेक्टर खोलकर आप चिन्हित करते वो सब सामने है। एग्रीकल्चर रोड मैप जो हमारा है, जिसमें एग्रीकल्चर, एलाइड सेक्टर सब और एग्रीकल्चर के लिए जितनी आवश्यकता है कीजिए हर चीज का आकलन कीजीए तो एग्रीकल्चर के लिए सिंचाई के लिए, बिजली की जरूरत है। तो बिजली भी उसमें शामिल है हमारे रोड मैप में कि कैसे हम एग्रीकल्चर के लिए डेडिकेटेड प्लान बनायेंगे और उस काम के लिए हम निधि उपलब्ध करायेंगे। तो ये सारी चीजें उसमें शामिल है। एग्रीकल्चर के लिए जब भी हम सिंचाई की बात करते हैं तो जो मेजर इरिगेशन्स स्किम्स है, सिर्फ उस बात के लिए माइनर इरिगेशन्स स्किमस के लिए, ड्रिफ्ट इरिगेशन्स ट्यूबेल्स के लिए अपनी स्किम बनाई गयी है, ट्यूववेल्स के लिए। तो उसमें बैंकों की दिलचस्पी नहीं थी। तो हर वो सेक्टर एग्रीकल्चर का, अब पावर सेक्टर है, पावर मेकेनाइजर सेक्टर तो उसके लिए आवश्यकता है। तो हर चीज में,

उसके प्रोसेसिंग के लिए फुड प्रोसेसिंग के नाम से आप जानते होंगे। एग्रीकल्चर सेक्टर का प्रोसेसिंग से भी बहुत लाभ है। वो काफी वैल्यू एडिशन करता है। एम्पलायमेन्ट जेनेरेट करता है। और कुल मिलाकर के जी.डी.पी. में वृद्धि करता है। तो इस प्रकार से एग्रीकल्चर सेक्टर एक व्यापक श्रेणी है पॉल्ट्री है। हर चीज इसमें शामिल है। तो इन सभी क्षेत्रों में उदार होना चाहिए। और बिहार जैसे राज्य में जिसमें स्टेट अपनी तरफ से बहुत ऊँची है। हम सिर्फ कह नहीं रहे है आपको कि आप ये कीजिए, या कुछ खास। हम लोग तो यह कह रहे कि हमलोग अपनी तरफ से कोशिश कर रहें है। इसमें अगर बैंकों का योगदान होता है तो हमारा जो ग्रोथ है या जो अभी ग्रोथ रेट है वो सस्टेनेबल रहेगा। बढ़ेगा भी और सस्टेनेबल रहेगा। क्योकि इसलिए कि हम ग्रोथ रेट के बारे में बहुत आगे जा चुके है। डबल डिजिट ग्रोथरेट हमारा आगे चल रहा है। त डबल डिजिट ग्रोथ रेट है जी.डी.पी. का तो वैसी स्थिति में तो अगर एग्रीकल्चर सेक्टर जिसपर 76 परसेन्ट लोग डिपेन्डेड है। तो इसके अलावे माइक्रोफाइनानसिंग का सेक्टर है। अब हमलोगों ने लोगों के बीच में जो काम किया है खासकर के सेल्फ हेल्प (SHG) ग्रूप्स बनाये हैं। हमारे यहां विलम्ब से काम शुरू हुआ है। लेकिन जो काम शुरू हुआ उसका जो मॉडल है, सबस्ट्रेक्ट है। और गवर्नमेन्ट ऑफ इन्डिया ने जो अंतोगत्वा हमारा जीविका का मॉडल था सेल्फ हेल्प (SHG) ग्रूप्स का उसी को आजिविका के मॉडल के रूप मे स्वीकार किया। तो नेशनल लाइवलीहुड मिशन बना और उसके लिए उसमें जो प्रोग्राम बनाया गया है तो बिहार में जा प्रयोग हुआ है। सेल्फ हेल्प (SHG) ग्रूप का पहले वर्ल्ड बैंक से असिसटेन्स लेकर. ऋण, लेकर हमलोगों

ने छः दिनों में उसकी शुरूआत की थी तो वहां से जो शुरूआत हुई है और पूरे बिहार में उसने कवर किया है। और हमारा लक्ष्य है कि हम पांच साल के अन्दर 10 लाख सेल्फ हेल्प (SHG) ग्रूप का गठन करें। तो 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप का गठन जब करेंगे तो आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने परिवार उसमें इन्वोल्व होंगे कितनी संख्याएं इन्वोल्व होंगी। एक सेल्फ हेल्प ग्रुप में अगर आप मिनिमम ग्यारह मेम्बर को रखेंगे तो एक करोड़ 10 लाख मेम्बर होंगे। तो यानि एक करोड़ 10 लाख परिवार और उसमें पांच से गुणा करिये छः करोड़, या पांच करोड़ पच्चास लाख लोग यानि पूरी आधी आवादी कवर होती है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के गठन की एक महत्वाकांक्षी योजना है। तो इसमें अब जब काम हो रहा है। हमारे यहां क्वालिटी के साथ काम इम्पैक्ट कर रहा है। अब ये जो जीविका का मॉडल अपनाया जो पहले से सेल्फ हेल्प ग्रुप में थी। चाहे वो ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित जिला स्तर पर जो डी. आर. डी. ए. था उसके माध्यम से या फिर विमेन डेवलपमेन्ट कॉरपोरेशन के माध्यम से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप बने थे। उन सबों को माइग्रेट कराया और एक ही अम्ब्रेला में अब ये पूरा आजिविका के अन्तर्गत सब सेलफ हेल्प ग्रुप को डाला तो 3 लाख से अधिक ग्रुप का फॉरमेशन हो चुका है। अब 17 दिन का टारगेट देंगे 10 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप को तो ये वायेबुल बनें। तो इस लिए जरूरी है, आपका जो क्रेडिट का है पहले से देने का तरीका कि साहब पहला क्रेडिट लिंकेज। और दूसरा क्रेडिट लिंकेज तो पहला क्रेडिट लिंकेज आप 50 हजार देते है और दूसरा 1 लाख देते हैं। तो हमारा सुझाव होगा कि पहला क्रेडिट लिंकेज 1 लाख रूपये का हो और दूसरा क्रेडिट लिंकेज 2 लाख

रूपये का हो। वैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को राज्य सरकार की तरफ से भी कहीं काम दिये जायेगे। हमलोगों ने कई स्किम्स उनके माध्यम से क्रियान्वित करना शुरू कर दिया है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप को वायेबल बनाने के लिए, सक्षम बनाने के लिए हमलोगों ने कई कदम स्वयं उठायें हैं। और ऐसी परिस्थिति में अगर बैंकों का भी क्रेडिट लिंक मिलता है तो सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत ही वायेबल हो जायेंगी। और जो हमारा लक्ष्य है 10 लाख ग्रुप बनाने का ये लक्ष्य का विस्तार हो सकता है। और ज्यादा ग्रुप्स बन सकती है। तो इस प्रकार मेरा एक सुझाव होगा इस एस.एल.बी.सी. की मिटिंग में कम से कम सेल्फ हेल्प ग्रुप के बारे में विचार करिए। फर्स्ट क्रेडिट लिंकेज और सेकेण्ड क्रेडिट लिंकेज दोनों का लिमिट आप बढ़ाईए। एक मेरा ये सुझाव होगा आप लोगो से। दूसरी बात है कि ये बात बार बार आ रही है कि और मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं जब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के केन्द्रीय निदेशक ने स्वयं कुछ बांते कहीं है। तो मैं नहीं समझता हूँ कि मुझको ज्यादा कहने की जरूरत है। उन्होंने तो एक एक बात स्वयं कही है। तो क्षेत्रीय निदेशक ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जब क्षेत्रीय निदेशक ने जो बात स्टेट लेवल बैंकर्स की मिटिंग में कही है उसी को मान लिया। उसी के हिसाब से चलिए। अब बैंक ब्रांचेज का सवाल है। देखिए हमलोग हर बार आपलोगों के समक्ष इस बात को रखते है। हमारे यहां 8400 से ज्यादा ग्राम पंचायत है अब 5298, फाइव थाउजेण्ड टू हण्ड्रेड नाइन्टी एट पंचायत अभी भी है जहां कोई बैंक की शाखा नहीं है। अब ग्राम पंचायत और एक बात आप जान लिजिए यहां पर सब लोग बैंक के अधिकारी है आप सबको मालूम होगा। ग्राम पंचायतों की संख्या पोपुलेशन के लिहाज से

कम है। हमारे यहां अब वो संख्या बढ़ रही होगी यानि जो पिछला चुनाव हुआ है, उस वक्त के हिसाब से हम बता रहें है। 12 थाउजेण्ड का पोपुलेशन है। 8 हजार वोटर्स है। और वो संख्या, अब वो और बढ़ रही है। अब ये पंचायती राज संस्थाओं का भी इस टर्म का उनका भी आखिरी साल चल रहा है। नेक्स्ट इयर उनका भी इलेक्शन डयूज है। तो वैसी स्थिति में उनकी संख्या, मतदाताओं की संख्या बढ़ चुकी होगी। जब डिलीमिटेशन हुआ और पंचायतों का गठन किया गया उस समय के हिसाब में 8 हजार मतदाता एवरेज 12 हजार पोपुलेशन उस हिसाब से हमारा ग्राम पंचायत कहिए। ये दूसरे राज्यों की तरह ग्राम पंचायत हमारा नहीं है। जहां कम पोपुलेशन पर ग्राम पंचायत गठित की है। जो नम्बर हम बता रहें है तो दूसरी जगहों पर और बड़ी ग्राम पंचायत है। तो अन्य राज्यों के ग्राम पंचायत से हमारे राज्य की ग्राम पंचायत की तुलना साइज में नहीं की जा सकती है। इस लिए और भी ज्यादा आवश्यक है कि यहाँ बैंक की शाखाएं होनी चाहिए। अब हर चीज हमलोग कह रहे हैं कि बैंक के माध्यम से हो। हमने तो प्रारंभ में भी शुरू किया था। साईकिल योजना, पोशाक योजना लड़कियों के लिए। सब कुछ कोशीश की, सफलता नहीं मिली। उनके एकाउंटस नहीं खुल पाएं। तो परेशानी होने लगी। तो फिर एक तिथि निर्धारित करके हमलोगों ने सीधे हाथ में पैसा बाँटना शुरू किया इस स्किम से। हमलोग तो चाहते थे कि हमारी सारी स्किमों को बैंक के माध्यम से चलाएँ अब 2007 में जो फ्लड आया था। उसमें 2.5 करोड़ लोग प्रभावित थे। हमारे यहां बाढ़ से प्रभावित थे। और उस समय जो कुछ हमने रिलिफ का वितरण किया था। तो राज्य के अलावे या फसल की फुल सबसीडी

हमलोगों ने दी थी। तो वो सब चाहते थे, लेकिन उसमें भी बड़ी कठिनाई आई। वही दृश्य 2008 में कोशी की आपदा के बाद एक बार दिखा। तो अब जब हर चीज अब लोग चाहते है यहां हो। अब एक–एक चीज का अब आपने जन–धन योजना का प्रचार किया है काफी तेजी से। और इतने खाते खुले। अभी भी वो सब खाते आपके ननफंक्शनल है, ज्यादातर खाते। जो आपके अकांउन्ट्स से हो रही है। यानि अकांउन्ट खुल गया लेकिन उसमें कोई ट्रांजेक्शन नहीं हो रहा है। और आपने ये चिंता प्रकट की। उन सबको चलायमान बनाया जाय, फंक्शनल बनाया जाय। तो आप हर चीज आप बैंक अकाउंट के माध्यम से करना चाहते हैं। तो वैसी परिस्थिति में तो बैंकों की सहायता होनी चाहिए। अब इस साल भी जो आपदाएं आई है। कई प्रकार की आपदाएं आई है। हमारे यहां सबसे पहले फसल क्षति हो गयी ओला वृष्टि से। अति वृष्टि, ओली वृष्टि और फरवरी में बहुत ठंड पड़ी तो दो महिने फसल को अधिक बरबाद किया। इसके बाद कुछ इलाकों में साइक्लोनिक स्टोर्म आ गया। और फिर इसके बाद, इसके बाद भूकम्प, भूकम्प तो आते ही जा रहे हैं। यानि हमलोग झेलते ही जा रहे है। लेकिन जहां तक फसल क्षति का सवाल है। फसल क्षति या तो ओला वृष्टि से या फिर आंधी–तूफान से या चक्रवाती तूफान से और ये निरंतर है। तो आखिरकार उसका हमलोग आकलन करते हैं। और जो भारत सरकार ने तय किया है, डिजास्टर के मामलों में जो, राहत प्रदान की गयी। नोर्मस तय की है फसल का जो भी नुकसान होगा। फसल का तो 50 प्रतिशत डैमेज होगा तब वो अगली फसल के लिए हम इनपुट सब सिडी देंगे। अब तो वो हो गया कि अगर 50 प्रतिशत डैमेज होगा तब अगली फसल के

लिए इनपुट सबसिडी देंगे। तो कितनी बड़ी संख्या है किसानों की, जिनको लाभ पहुंचाना है। और तब हमलोग ये कर रहे है। नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर स्किम, एनईएफटी के माध्यम से हमलोग कर रहे है। तो जब आपकी बैंक की शाखाएं रहेंगी। लोग कार्यरत रहेंगे। तब तो किसानों को इसका फायदा होगा। अब जो दूसरी बात हम आपलोगों के सामने रखना चाह रहे हैं कि साहब एनइएफटी के माध्यम से जो हमलोग पैसा दे रहे है। फसल क्षति के बाद, फसल क्षति के तौर पर। ट्रांसफर कर रहे उनको। तो ये पता चल रहा है कि काफी विलम्ब हो रहा है। उनके खातों मे पैसा पहुचने में। अब ये हमारे लिए सबसे, ये ताजा, बिल्कुल हाल की समस्या है, जो करेंट है, चल रहा है, अभी ये आरटीजीएस के माध्यम से ट्रांसफर हो रहे हैं। अभी ट्रांसफर हो रहे है। अब ये शिकायत मिल रही है कि भई यहां से तो हमलोगों ने ट्रांसफर कर दिया लेकिन वो उसके खातों में पहुंचाने में विलम्ब हो रहा है। त ये आपलोगों को देखना पड़ेगा। सारे बैंक के प्रतिनिधि यहां पर उपस्थित है। इसलिए ये इंतजाम करिए कि ये जो NEFT से ट्रांस्फर हो रहा उनके खातों में तत्काल पहुंच जाये। और अगर आपकी बैंक की शाखाएं खुली होंगी। तो किसानों को जरूरत के मुताबिक पैसे निकालने में सहुलियत होगी। अब आपके ब्रांचेज ही इतने पंचायतों में नहीं है अब इसके अलावे ब्रांचेज हैं भी तो इसको हम जो कहते है वो कम है। अब उसके बाद स्थिति ये है कि वन मैन ब्रांच, एक ही आदमी आपके वहाँ है। एक ही आदमी के जिम्मे सारा काम है। तो मौलिक तौर पर इसके बारे में सोचना पड़ेगा कि एक ऑफिसर एक ब्रांच में रहेगा और इतने प्रकार की गतिविधियां है प्रतिदिन। आपने अभी कहा कि हमलोग अभी अटल

पेंशन योजना के बारे में लोगों को जानकारी दे रहे है। ये सब आप जानकारी देंगे। और उसमें में भी ज्यादातर बैंक में एक आदमी आपका है। और स्किमस बढ़ती चली जा रही है। हमलोग सब ट्रांसफर करते जा रहे है। स्ट्रेन्थ बढ़ाने की बात बहुत जमाने से चल रही है। उसका ही नाम बदल करके और भी कई स्किमस को चलाने की कोशिश हो रही है। ये अच्छी बात है होना चाहिए। हमारा अधिकार है एक एक नागरिक का बैंक का खाता खोलना चाहिए। बहुत जमाने से हमलोग सोच रहे है। लेकिन बैंक का खाता खुल जाये और एक्सेस भी तो होना चाहिए बैंक तक। अब देहात लोगों को मीलों चलकर बैंक में पहुंचना पड़ेगा। और फिर ये जो ट्रांसफर है उनके लिए जो स्किम्स चलती है। उनके पैसे का ट्रांसफर हो उसमें विलम्ब होगा। अब एक व्यक्ति कितनी बार बैंक की शाखा में जायेगा। एक आदमी का ब्रांच है। उसकी भी अपनी सीमा है। एक व्यक्ति अकेला कितनी देर काम करेगा।